

भारत सरकार  
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 292**

27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की औसत आय

292. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की औसत आय का हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि घरेलू उपभोग व्यय संबंधी अंतिम राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) 68वां दौर (जुलाई, 2011-जून, 2012) द्वारा किया गया था और उसके बाद कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसके बाद कोई सर्वेक्षण नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का सर्वेक्षण विंग अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि, इन सर्वेक्षणों में देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की औसत आय का अनुमान नहीं लगाया जाता है।

(ख) से (घ): कोविड-19 महामारी परिदृश्य के सामान्य होने के बाद उपभोक्ता व्यय पर 2022-23 और 2023-24 के दौरान एक के बाद एक करके दो सर्वेक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में, घरेलू उपभोग व्यय (एचसीईएस: 2022-23) पर नवीनतम सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2022-जुलाई, 2023 के दौरान किया गया था। इससे पहले, ऐसा पिछला सर्वेक्षण जुलाई, 2011-जून, 2012 की अवधि के दौरान एनएसएस के 68वें दौर में किया गया था। एचसीईएस 2022-23 की रिपोर्ट जून, 2024 में जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, एचसीईएस 2023-24 के लिए डेटा संग्रह के संबंध में क्षेत्र कार्य अक्टूबर 2024 में पूरा हो गया है।